



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 166 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, अगस्त, 07

2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुनर्प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61/1999-FC (Pt,VII) दिनांक-13.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या-241/12-1 दिनांक 30.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:-

आपत्ति	उत्तरालेख
i. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File की सी.डी प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है।
ii. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:	
a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 है० लिया गया है। जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था। जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।
b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर०डी० 2200 मी० तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही एन०एच०पी०सी० द्वारा पावर स्टेशन तक नहर के किनारे निर्मित की गई सड़क का प्रयोग एन०एच०पी०सी० द्वारा किया जाता है। साथ ही आवंटित बॉध क्षेत्र में एन०एच०पी०सी० द्वारा समय-समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है।



आपत्ति	उत्तरालेख
c. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online.	प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ छाया प्रति संलग्न है।
d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lazga Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्र संख्या 173/ 12-1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा-लग्गा-बग्गा-फिलिभीत टाइगर कॉरिडोर के सम्यन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
<b>iii. Examination of the Mining scheme revealed the following:</b>	
a. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 है० है। जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 है० तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 है० है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25-25% छोड़ा जाता है एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 है० क्षेत्र दर्शित है।
b. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 वर्षीय माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।
c. Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।
d. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्र में दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेष भाग में खनन कार्य किया जाता है इस कारण केवल 192.345 है० क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।
e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 वर्ष की खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 05 साल हेतु खनन योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।
iv. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, जो उनके पत्र के साथ संलग्न है।

आपत्ति	उत्तरालेख
v. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guideline में 2016 अनुरूप है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
vi. Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure -III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
vii. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0वी0एम0 की बिक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभाग को दिया जाता है विगत वर्षों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
viii. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 166 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक-241/12-1 दिनांक 30.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।





# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

01-8-22



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 241 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 30/07/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुनर्प्रस्ताव FP/UK/Min/154581/2022 में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61/1999-FC (Pt,VII) दिनांक-13 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी (वन निगम) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपने पत्र 297/वन स्वीकृति/दिनांक-30.06.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया था। प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की संकलित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<p>1- Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File सी.डी में संलग्न हैं तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-अ)</p>
<p>i. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:</p>	
<p>a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.</p>	<p>उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 हैक्टे0 लिया गया है। जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था। जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।</p>

ग्रा.सि.0

व.सं.0


कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त  
नैनीताल  
बंजीकरण सं. 614 .....  
बंजी. सं. 12-1 .....  
दिनांक 2-8-22

<p>b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-via violation of Forest (Conservation) Act, 1980.</p>	<p>टनकपुर बैराज रो अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर0डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज रो डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबंधित है साथ ही एन0एच0पी0सी0 द्वारा पावर स्टेशन तक नहर के किनारे निर्मित की गई राइक का प्रयोग एन0एच0पी0सी0 द्वारा किया जाता है साथ ही आवंटित बंध क्षेत्र में एन0एच0पी0सी0 द्वारा समय-समय पर बंध की गरमगत कार्य किया जाता है। (छायाप्रति संलग्न-1)</p>
<p>c. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online.</p>	<p>(छायाप्रति संलग्नक-2)</p>
<p>d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी की पत्र संख्या 173/ 12-1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा-लगगा-बग्गा-पीलीभीत टाइगर कॉरिडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-ब)</p>
<p><b>ii. Examination of the Mining scheme revealed the following:</b></p>	
<p>e. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.</p>	<p>आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 हैक्टरे है। जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 हैक्टरे तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हैक्टरे है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25-25% छोड़ा जाता है। एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 हैक्टरे क्षेत्र दर्शित है।</p>
<p>f. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.</p>	<p>इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 व र्तीय माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।</p>
<p>e. Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.</p>	<p>इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।</p>
<p>f. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.</p>	<p>खनन क्षेत्र में दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेष भाग में खनन कार्य किया जाता है इस कारण केवल 192.345 है0 क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।</p>



g. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	02 वर्ष की खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 05 साल हेतु खनन योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।
h. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिपोर्ट संलग्नक की जा रही हैं। (छायाप्रति संलग्नक -5)
i. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guidelin मे 2016 अनुरूप है, उनके द्वारा दिया गया पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -6)
j. Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure -III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -7)
k. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की बिक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभाग को दिया जाता है विगत व र्गों का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -8)
l. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक -8)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।  
(को प्रतियोगिता)

भवदीय,  
  
(बाबू लाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



टनकपुर (शारदा) वन परिसर, आई नम्बर- 8, जनापद- चम्पावत, E-mail- roshardaraoffice@gmail.Com

पत्रांक :- 133 / 7-1,

टनकपुर,

दिनांक:- 26 / 07 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,

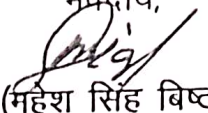
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय :- हरतान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक से सादर अवगत कराना है, कि शारदा वन क्षेत्र के अन्तर्गत F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान के सापेक्ष के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

  
(महेश सिंह बिष्ट)

वन क्षेत्राधिकारी,  
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर

सं. 1- (28)

वर्ष	प्रभाग का नाम	परियोजना का नाम जिसमें वन भूमि हरणाचरण के माध्यम शक्तिपुरक वृक्षारोपण संचालित किया गया है	हरणाचरित वन भूमि	हरणाचरित वन भूमि के माध्यम शक्तिपुरक वृक्षारोपण				शकलता प्रतिशत	व्यय धनराशि	अवशेषित
				रेल का नाम	खेत का नाम	शक्तिपुरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (हे० मं०)	संचालित क्षेत्रों की संख्या			
2015	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	F.No- 8-6/1/999 FC (P-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टयर)	-	शारदा	शारदा द्वितीय शीट शारदा टापू संख्या 35 व 38 के मध्ये	25	12500	70%	2014000.00	-
2016			शारदा	शारदा टापू संख्या 42	16	16000	75%	889688.00	-	
2016			शारदा	शारदा टापू संख्या 36	28	28000	90%	1385457.00	-	
2016			शारदा	शारदा टापू संख्या 43 व 44 के मध्ये	16	16000	80%	1030047.00	-	
2016			शारदा	शारदा टापू संख्या 37 व 38	63	63000	78%	3218523.00	-	
2020			शारदा	शारदा टापू संख्या- 36	20	20000	85%	1913554.00	-	
2020			शारदा	शारदा टापू संख्या- 34 व 35 मध्ये	20	20000	80%	2007748.00	-	
2021			शारदा	शारदा टापू संख्या- 35 व 36 मध्ये	20	22000	90%	2000351.00	-	
2021			शारदा	शारदा टापू संख्या- 37	20	22000	91%	1617520.00	-	
2022			शारदा	शारदा टापू संख्या- 37	21	23100	100%	1965091.00	-	
2022	शारदा	शारदा टापू संख्या- 01	20	22000	100%	2020725.00	-			

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

वर्षवार की उर्वरित वृक्षारोपण की कार्यवाही का प्रमाण पत्र है।  
शारदा नदी के उपखनिज का चुगान।  
वृक्षारोपण कार्य पूर्ण रूप से किया गया है।  
वृक्षारोपण की कार्यवाही का प्रमाण पत्र है।



संलग्न-37)

2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-36	भाग-01	15	16500	100%	2004463.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-41	भाग-01	14	15400	100%	1463937.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-35 एवं 37 मध्ये	भाग-01	22	24200	100%	2095439.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-35 एवं 37 मध्ये	भाग-02	22	24200	100%	2140311.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-14	भाग-02	7	7700	100%	1141345.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-36	भाग-02	21	23100	100%	2139503.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-13	भाग-02	15	16500	100%	903688.00
2022		शारदा		शारदा टापू	सं०-13	भाग-02	385	392200	—	31951400.00

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111)  
Date- 11-02-2013  
शारदा नदी के उपखनिज का चुगान।  
(384.69 हेक्टर)

(महेश सिंह बिष्ट)  
वन क्षेत्राधिकारी,  
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर।

(महेश सिंह अधिकारी)  
वन दरोगा / अनुभाग अधिकारी,  
शारदा टापू अनुभाग।

(पुष्पेन्द्र सिंह राणा)  
वन बीट अधिकारी,  
शारदा टापू द्वितीय बीट।

वर्तमान में कृत्रिम नुदा कार्य की दस्तावेज व्यव की नदी है। वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वनीकरण की दस्तावेज प्राप्त नही हुये है।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल: dfohdw@gmail.com

पत्रांक 173 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक

20.07.2022

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
राजपुर रोड,  
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:-

जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत स्थित शारदा नदी में 384.09 हे० क्षेत्र के चुगान कार्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ MIN/154581/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा 384.09 हे० क्षेत्र में उप-चुगान कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि वर्ष फरवरी 23 में समाप्त हो रही है। पुनः आगामी दस वर्ष का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या-8-01/1999-एफएसी. (पार्ट-II) दिनांक-13 मई 2022 द्वारा प्रकरण में आपत्ति उठायी गयी है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति उठायी गयी है कि उक्त क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर की सीमा से लगभग 3 कि.मी. (1.6 कि.मी. हवाई दूरी) की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित प्रस्ताव पर मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया प्राप्त की जाय। जिसे मंत्रालय के विचारार्थीन प्रस्तुत किया जाएगा।

महोदय यद्यपि प्रश्नगत क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर से 3.00 कि.मी. की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं एवं पूर्व में भी 10 वर्षों के लिए उप चुगान की अनुमति प्रदान की गयी थी। यह भी अवगत कराना है कि उप चुगान से वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में उठायी गयी आपत्ति पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वाक् लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी